(ख) क्या यह सच है कि "क्विज" कार्यक्रम केवल अंग्रेजी में प्रसारित किया जाता है और इस कार्यक्रम के विषय शहरी जनसंख्या की आवश्यकताएं पूरी करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करने की योजना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) :(क) जी, नहीं। लक्ष्य श्रोताओं के लिए सभी ग्रामीण कार्यक्रम श्रोताओं के रूझान आवश्यकताओं तथा सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नियोजित तथा निर्मित किए जाते हैं। यह दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण युवकों, महिलाओं तथा बच्चों के लिए निर्मित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर भी लागू होता है।

(ख) जी, नहीं दूरदर्शन कई क्विज कार्यक्रमों को हिन्दी में टेलीकास्ट करता रहा है। इन सभी कार्यक्रमों का नियोजन करते समय समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं तथा रूचियों को ध्यान में रखा जाता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का मूल्यांकन

3748. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) के कार्यक्रम का मूल्यांकन करने का विचार रखती है ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि लाभान्वित लोगों को पूरी धनराशि प्रदान नहीं की गई और कई मामलों में तो कुछ भी धनराशि प्रदान नहीं की गई ; और

(ग) क्या सरकार बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, और असम की स्थिति की महाराष्ट्र और गुजरात की स्थिति से तुलना करेगी और बताएगी कि इस सम्बन्ध में वहां क्या-क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन समय-समय पर कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं में निर्धारित मासिक/त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है। इसके अलावा, कुछ राज्यों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन किए जाते हैं। हाल ही में देश में 12 माह की अवधि के भीतर सभी जिलों को कवर करने के लिए कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन शुरू किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों पर लगे श्रमिकों को मजदूरी का कम भुगतान करने और मजदूरी का भुगतान करने में विलम्ब होने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है।

(ग) विभिन्न राज्यों के तुलनात्मक निष्पादन का मूल्यांकन राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय औसत और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तिमाही लक्ष्यों के सन्दर्भ में प्रत्येक तिमाही में किया जाता है।

पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा पर "दुग्ध क्रांति" का प्रभाव

3749. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "दुग्ध क्रांति" का बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम और उडीसा राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इन राज्यों में यह परियोजना आरम्भिक चरण में है अथवा अभी आरम्भ की जानी है ;

(ख) विदेशों से उपहार स्वरूप प्राप्त हुई दुग्ध निर्माण वस्तुओं, जैसे दुग्ध पाउडर

और बटर आयल आदि की मात्रा कितनी है और उनका मूल्य कितना है ; और

(ग) भविष्य मे उपहार स्वरूप मिलने वाली इस प्रकार की सामग्री की क्या स्थिति है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा (क) बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा के राज्यों मे आपरेशन फलड की उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिये)**

(ख) 1985-86 से 1987-88 (सितम्बर, 1987 तक) (अनन्तिम) तक उपहार स्वरूप प्राप्त जिन्सों का ब्योरा इस प्रकार है :--

(आंकड़े मी० टीटरी में)

वर्ष	स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण	सम्पूर्ण दुग्ध चूर्ण	बटर आयल	बटर
1985-86	9516	—	2813	3492
1986-87 (अनन्तिम)	5879	10	344	800
1987-88 (सितम्बर 87 तक) (अनन्तिम)	10000	—	2032	2400

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय आपरेशन फलड के लिए खाद्य सहायता कार्यक्रम, 1987 के अंतर्गत 12000 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूण और 4000 मीटरी टन बटर आयल की सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया है। उक्त सामग्री जहाज से लायी गई है/लायी जा रही है। इसके अलावा करीब 5200 मीटरी टन बटर आयल का आयात करने का प्रस्ताव है जिसके लिए भूतपूर्व भारतीय डेरी निगम को दान के रूप में अमरीकी सहायता स्वीकृत हो गई है। इसके अतिरिक्त अमरिका के चीनी कोटा क्षतिपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली मदर डेरी का फल और सब्जी यूनिट करीब 2305 मीटरी टन बटर आयल प्राप्त कर रहा है।

विवरण

बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा के राज्यों में आपरेशन फलड कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	ब्यौरा	1984-85	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5
बिहार	किसान सदस्यो द्वारा संगठित डेरी सहकारी समिति (हजार)	765	1030	1218
	औसत दुग्ध अधिप्राप्ति (हजार किलोग्राम प्रति दिन)	15.83	22.18	44.47
	ग्रामीण दुग्ध परिसंस्करण क्षमता (हजार लिटर प्रति दिन)	22.63	23.96	76.13
		120	225	287

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	किसान सदस्यों द्वारा संगठित डेरी सहकारी समिति (हजार)	1978 49.48	1024 56.45	1144 64.96
	औसत दुग्ध अधिप्राप्ति (हजार किलो-ग्राम प्रति दिन)	33.15	35.34	47.23
	ग्रामीण दुग्ध परिसंस्करण क्षमता (हजार लिटर प्रति दिन)	100	100	100
असम	किसान सदस्यों द्वारा संगठित डेरी सहकारी समिति (हजार)	124 5.93	125 1.44	125 1.44
	औसत दुग्ध अधिप्राणित (हजार किलो ग्राम प्रति दिन)	1.96	4.65	3.72
	ग्रामीण दुग्ध परिसंस्करण क्षमता (हजार लिटर प्रति दिन)	10	10	10
उड़ीसा	किसान सदस्यों द्वारा संगठित	285	352	391
	डेरी सहकारी समिति (हजार)	11.22	14.03	17.58
	औसत दुग्ध उत्पादन (हजार किलो-ग्राम प्रति दिन)	5.40	8.79	17.38
	ग्रामीण दुग्ध परिसंस्करण क्षमता (हजार लिटर प्रति दिन)	10	70	70

"डेलीज फस एंड क्रंच" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

3750. **श्री अजीत सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर, 1987 के "इकानामिक टाईम्स" में प्रेस कार्पोरेशन के संबंध में "डेलीज फस एंड क्रंच" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) सरकार ने समाचार को देखा है।

(ख) सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है तथा इसके कार्य संचालन में हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि यह निजी क्षेत्र में है। तथापि, सरकार प्रेस के संतुलित संवर्धन के लिए विभिन्न सेवाएं तथा सुविधाएं इस ढंग से उपलब्ध करा रही है कि उससे उसके कार्य संचालन हस्तक्षेप न हो।

Charging rent from allottees of Government accommodation

3751. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that when the allottees of Government quarters are on leave (E.L.) official tour or out of station have been charged rents and other fees on faiture to take the possession of the quarters on account of said reasons, if so, what are the norms in this regard;